कश्मीर के मामले में पश्चिमी देशों के बयान

666. **श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और कुछ अन्य पश्चिमी देश अपने निहित स्वार्थों के लिए कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के विषय में गलत बयानी कर 1972 के शिमला समझौते को सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते हैं;

(ख) क्या पश्चिमी देश कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का बहाना बनाकर वास्तविक मामले को गलत दिशा दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर अपना क्या वक्तव्य दिया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) शिमला समझौते की प्रासंगिकता को एक ऐसी रूपरेखा के तौर पर, जिसके दायरे में भारत और पाकिस्तान के बीच के अनसुलझे सभी मसलों को सुलझाया जा सकता है, अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार किया गया है जिनमें अमरीका और दूसरे पश्चिमी देश भी शामिल हैं। हालांकि उनमें प्रच्छन्न रूप से यह सोचा जा रहा है कि शिमला समझौते के आधार पर कश्मीर के मसले को सुलझाने में प्रगति नहीं हुई है लेकिन यह सोच भी विकसित हो रही है कि इसका समाधान या तो शिमला समझौते के जरिये निकलना चाहिए या ऐसे दूसरे माध्यमों से जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रोत्साहन प्राप्त हो, अमरीका का मत यह नहीं है कि शिमला समझौते पर सफलतापूर्वक अमल नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह है कि इस पर अमल नहीं हुआ है और इसीलिए दूसरे तरीकों पर विचार किया जा सकता है।

(ख) जम्मू और कश्मीर के बारे में ठोस यथार्थ को और स्थिति को पूरी तरह समझे बिना वक्तव्य दिए गए हैं।

(ग) सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों को शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय बातचीत के जरिए दूर किया जाना है। सरकार जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध घटनाओं के तथ्यों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत और आवश्यक उपाय करती रही है और आइन्दा भी करती रहेगी।

परमाणु निरस्त्रीकरण नीति के अधीन परमाणु अस्त्रों का नष्ट किया जाना

667. **श्री ब्रह्मदेव आनंद पासवान :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार कश्मीर के संदर्भ में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में भारत पर दबाव डाल रही है; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" में हो तो क्या भारत सरकार इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करना चाहेगी; यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) अमरीकी नाभिकीय अप्रसार संधि का न्यासी राज्य है और उसने इसके प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की है। ऐसा करने में उसने उन सभी देशों का जो अभी तक इस नाभिकीय अप्रसार संधि के सदस्य नहीं बने हैं, इस नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया है।